भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 276 *

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 5 जनवरी, 2018/15 पौष, 1939 (शक) को दिया जाने वाला है।)

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर

*** 276. श्रीमती पूनमबेन माडम:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2018 में 7.2 प्रतिशत तथा अगले वर्ष बढ़कर 7.4 प्रतिशत होने की सम्भावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर शुरू किए गए सार्वजनिक निवेश से भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार वृद्घि हुई है;

(ग) क्या सरकार तथा सैंट्रल बैंक के नीतिगत उपायों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आत्मविश्वास काफी बढ़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ में किए गए नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क): से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्रीमती पूनमबेन माडम द्वारा पूछे गए, शुक्रवार, 05 जनवरी, 2018 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 276* के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) : संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकॉनोमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2018-19 में 7.2 की दर से तथा वर्ष 2019-20 में 7.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि भारत के संदर्भ में संभावना अत्यधिक सकारात्मक बनी हुई है जिसे निजी खपत, सरकारी निवेश तथा साथ ही चालू संरचनात्मक सुधारों द्वारा मजबूती मिल रही है।

(ख): कुल सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में सरकारी क्षेत्र (सरकारी वित्तीय तथा गैर-वित्तीय निगमों तथा सामान्य प्रशासन सहित) की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 के 21.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 22.0 प्रतिशत तथा वर्ष 2015-16 (नवीनतम वर्ष जिसके संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं) में आगे और बढ़कर 25.2 प्रतिशत हो गई है। मौजूदा मूल्यों पर जीडीपी में सरकारी जीएफसीएफ की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 6.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 7.4 प्रतिशत हो गई है। मांग पक्ष से जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के जीएफसीएफ का योगदान वर्ष 2015-16 में लगभग 20 प्रतिशत था।

(ग): भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए नीतिगत उपायों के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास में वृद्धि हुई है। हाल ही में मूडीज रेटिंग एजेंसी ने आने वाले समय में भारत में हो रहे निरंतर आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप भारत में विकास की संभावना में वृद्धि होने की प्रत्याशा से भारत के स्थानीय एवं विदेशी करेंसी जारी करने से संबंधित रेटिंग को बीएए2 से बढ़ाकर बीएए3 कर दिया है। विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग में 30 स्थानों का सुधार हुआ है और यह 100 वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम के अनुसार वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक 137 देशों में से 40वां था जो वर्ष 2014-15 में 144 देशों में से 71वें स्थान पर तथा वर्ष 2015-16 में 140 देशों में से 55वें स्थान पर होने की तुलना में सुधार को सूचित करता है। वर्ष 2016-17 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सकल अंतर्वाह 60.2 बिलियन अमरीकी डॉलर था जबकि वर्ष 2015-16 में 55.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा वर्ष 2014-15 में 45.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था। वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सकल अंतर्वाह 33.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का हुआ था जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में उच्च स्तर को सूचित करता है।

(घ): भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास में वृद्धि करने तथा इसकी विकास दर को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, परिवहन, विद्युत क्षेत्र एवं अन्य शहरी तथा ग्रामीण अवसंरचना के लिए ठोस उपाय करना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए व्यापक नीतिगत सुधार करना शामिल है। सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में भी अनेक उपायों की घोषणा की है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सस्ते मकानों को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करके अवसंरचना विकास में सहायता करना, राजमार्गों के निर्माण के लिए अधिक राशि का आवंटन करना तथा तटीय संयोजकता पर ध्यान देना शामिल है। राजमार्ग विकास के लिए भारतमाला परियोजना शुरू की गई है। सरकार ने बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के एक चरणबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की है जिसमें आगामी दो वर्षों के दौरान बैंकों को लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराना शामिल है। इससे बैंक अधिकाधिक ऋण देने के लिए प्रेरित

होंगे। शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन कानून अधिनियमित किया गया है ताकि शोधन अक्षमता से संबंधित समाधान समयबद्ध रूप में हल किया जा सके। विकास को प्रेरित करने के लिए अन्य उपायों में 50 करोड़ रु. तक के वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अपेक्षाकृत कम आयकर, डिजिटल अर्थव्यवस्था को पर्याप्त बढ़ावा देना शामिल है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने से व्यापार, व्यवसाय और संबंधित आर्थिक क्रियाकलापों के मार्ग की बाधाओं को दूर करके विकास की गति में तेजी लाने का एक उपयुक्त अवसर उपलब्ध हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 3 वर्षों (2015 से 17) के दौरान रेपो दर में 200 आधार अंकों की कमी की है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग प्रणाली में जोखिम को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में जोखिम वाली आस्तियों के पुनरूद्धार हेतु ढांचागत व्यवस्था करना तथा सूचना की एकसमानता न होने की स्थिति को कम करने के लिए बड़े ऋणों के लिए केंद्रीय सूचना निक्षेपागार को स्थापित करना शामिल है।

*****